



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1981/पौष 26, 1902

No. 25]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1981/PAUSA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1981

का. आ. 30(अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/80.—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 37(अ)/18-एफ बी/आई डी आर ए/75, तारीख 17 जनवरी, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 (च स) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पञ्चाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंको और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिनका मर्सर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत होनेवाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त बड़ा बी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1981 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है की और अवधि के लिए बड़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-च स की उपधारा 2 के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1981 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[एफ. सं. 2 (33)/79-सी. यू. एस.]

आर. एन. चोपड़ा, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1981

S.O. 30(E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No.

S.O. 37(E)181 B/IDRA/75, dated the 17th January, 1975 hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 16th January, 1981 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 8th October, 1981 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 8th October, 1981.

[File No. 2(23)/79-CUS]  
R. N. CHOPRA, Addl. Secy.